

108



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12048 निगरानी R-3142-III/14

दिनांक 17-9-14  
का को कोर्ट-दीवित  
का को प्रस्ताव  
17-9-14

- १- जगमोहन | पुत्राण जगन्नाथ
  - २- कल्याण सिंह |
- निवासीगण सेवड़ा, तेहसील सेवड़ा,  
जिला दतिया-म०प्र०।

----- प्रार्थीगण

विराध्व

- १- मध्यप्रदेश शासन,
- २- समस्त मुस्लिम समाज द्वारा इंदगाह  
कब्रिस्तान अमेट्टी, सेवड़ा, जिला दतिया।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विराध्व आदेश तेहसीलदार महोदय सेवड़ा जिला दतिया  
मध्यप्रदेश प्र०क्र० १०८/अ-१२।१३-१४ आदेश दिनांक १६-७-१४, अन्तर्गत  
धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आशा कानूनन सही नहीं है।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण न तो विधिवत् प्रीमाण  
की कार्यवाही ही की गई है और न विधिवत् जांच ही  
की गई है।
- ३- यह कि, प्रार्थीगण को हितवध्व होते ह्ये भी सुनवाई का  
कोई अवसर नहीं दिया गया है।
- ४- यह कि, धारा १२६ के प्रावधानों का भी वर्तमान प्रकरण में  
पालन नहीं किया गया है।

Handwritten signature and initials.

3

क्रमशः ---२



Handwritten notes and numbers on the right margin, including '236', '235', and '1.8.14'.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-3142-दो/2014

जिला-दतिया

जगमोहन व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के
31-05-2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</li><li>2. आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी एवं अनावेदक क्र. 2 की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित ।</li><li>3. यह निगरानी तहसीलदार सेवड़ा, जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 108/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19-07-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</li><li>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</li><li>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी सेवड़ा, जिला-दतिया को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</li></ol>	

3

(आर.के. जैन) 31/5/19  
सदस्य